

## न्यूज डायरी



लुहान्स्क के गवर्नर का दावा— क्षेत्र में घुसे रूस के 10 हजार सैनिक

एजेसी (वेब वार्ता न्यूज) कीव। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध अभी भी जारी है। कई दिनों से चल रहे इस युद्ध में यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। युद्ध अभी तक किसी नतीजे पर भी नहीं पहुंच सका है। ऐसे में रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। लुहान्स्क के गवर्नर सेरही गदाई ने दावा किया है कि रूस के करीब 10 हजार लड़ाके क्षेत्र में घुस गए हैं। सेरही गदाई ने बताया कि रूसी सैनिकों की कई यूनिट स्थायी रूप से लुहान्स्क में हैं। वे लगातार हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। रूसी सैनिक क्षेत्र में अपनी बढ़त बनाना चाहते हैं। इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेन्स्की ने पश्चिमी देशों से रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने की अपील की। जेलेन्स्की ने कहा कि पश्चिमी देश रूस से आख-मिचौली खेलना बंद करें और उस पर कड़े प्रतिबंध लगाएं जिससे बेमतलब का युद्ध खत्म हो सके। लीमन पर कब्जे को रूसी सेना की बड़ी सफलता माना जा रहा है। पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क और लुहान्स्क पर पूर्ण कब्जे के लिए रूसी सेना लगातार हमले कर रही है।

क्या बगावती तेवर अपनाकर रूस से तेल खरीदेगा पाकिस्तान?

एजेसी (वेब वार्ता न्यूज) इस्लामाबाद। दुनिया भर के दबाव के बावजूद भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदा है। अब पाकिस्तान भी भारत के नक्शे कदम पर चलना चाहता है। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने शुक्रवार को रूस से गेहूँ और तेल के आयात से इनकार न करते हुए कहा कि राष्ट्र के हित लिए सभी विकल्प खुले हैं। पीएम मोदी ने दुनिया के दबाव के बावजूद भी रूस से सस्ता क्रूड ऑयल खरीदा है। इमरान खान ने भी कई बार अपनी रैलियों में इस बात का जिक्र करते हुए भारत की तारीफ की है। माना जा रहा है कि इमरान के दबाव और महंगे पेट्रोल के कारण शबहाज शरीफ सरकार बगावती तेवर दिखाते हुए रूस से क्रूड ऑयल खरीद सकती है। पाकिस्तानी विदेश कार्यालय के प्रवक्ता असीम इफितखार ने शुक्रवार को कहा, शहमरी नीति स्पष्ट है। जहां भी हर अपने राष्ट्रीय हित देखेंगे उन रास्तों पर चलेंगे।

अफगान महिलाओं पर प्रतिबंध हटाने के लिए यूएनएससी के आह्वान को किया खारिज

एजेसी (वेब वार्ता न्यूज) काबुल। तालिबान जबसे अफगानिस्तान पर कब्जा किया है, उसका असली चेहरा सबके सामने आ चुका है। महिलाओं के हित, शिक्षा और नौकरी की आजादी की बात करने वाला तालिबान, अब अफगानिस्तान में महिलाओं का जीना दुश्वार कर रहा है। अपने नए-नए प्रतिबंधों में तालिबान सरकार महिलाओं पर कई तरह की पाबंदियां पहले भी लगा चुका है। इन सख्त नियमों के लागू करने पर यूएनएससी ने चिंता व्यक्त की थी। और तालिबान सरकार से महिलाओं पर लगे सभी सख्त कानून हटाने के लिए कहा था। तालिबान लड़ाकों ने यूएनएससी द्वारा अफगान महिलाओं के खिलाफ अपने सख्त कदम उठाने के आह्वान को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया है। अब्दुल कहर बलखी ने कहा, चूंकि अफगानिस्तान के लोग मुख्य रूप से मुस्लिम हैं, इसलिए अफगान सरकार इस्लामी हिजाब के पालन को समाज की धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाओं के अनुरूप मानती है।

पाकिस्तान में अभी तक मंकीपाक्स के टेस्ट की नहीं है सुविधा

एजेसी (वेब वार्ता न्यूज) इस्लामाबाद। दुनिया के कई देशों में मंकीपाक्स का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। भारत समेत कई देश बिना कोई केस के तैयारियों में जुट गए हैं। लेकिन पाकिस्तान में वायरस के नैदानिक परीक्षण तक की कोई सुविधा नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि देश में अभी तक मंकीपाक्स का कोई मामला सामने नहीं आया है लेकिन प्रकोप की स्थिति में नमूनों को परीक्षण के लिए विदेश भेजा जा सकता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ (एनआईएच) इस्लामाबाद ने बताया कि पाकिस्तान में अभी तक मंकीपाक्स का कोई मामला सामने नहीं आया है। मंकीपाक्स के मामलों के बारे में सोशल मीडिया पर चल रही खबरें गलत हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा स्थिति की बारीकी से निगरानी की जा रही है।

# चीन ने सोलोमन से किया क्वाड को चैलेंज तो फिजी ने दिखाई औकात!

झटका

10 छोटे देशों के साथ डील करने जा रहा चीन

एजेसी (वेब वार्ता न्यूज)

वाशिंगटन। फिजी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में शामिल हो रहा है। वाइट हाउस ने इसकी जानकारी दी। इसी के साथ फिजी चीन के बढ़ते क्षेत्रीय प्रभाव को कम करने के अमेरिकी प्रयासों का हिस्सा बनने वाला पहला प्रशांत द्वीप देश बन गया है। अमेरिका ने यह घोषणा ऐसे समय पर की है जब चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने फिजी सहित प्रशांत द्वीप देशों का व्यापक दौरा शुरू किया है। खबरों के मुताबिक वह 10 क्षेत्रीय देशों का दौरा करने जा रहे हैं कि जिसकी शुरुआत उन्होंने सोलोमन द्वीप से की है।

न्यूज एजेसी रॉयटर्स की खबर के अनुसार फिजी बीजिंग और वाशिंगटन के बीच प्रभाव के मुकाबले में एक तनावपूर्ण मोर्चा बनता जा रहा है। सोलोमन पहुंचे चीनी विदेश मंत्री प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के बेहद करीब स्थित 10 छोटे-छोटे देशों के साथ सुरक्षा व व्यापार समझौता करने जा



रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया सोलोमन में चीन के दखल को खतरा मानता है। ऐसे में चीन की इस चाल से ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका टेंशन में हैं।

हिंद-प्रशांत क्षेत्र की स्वतंत्रता को लेकर प्रतिबद्ध: वाइट हाउस ने आईपीईएफ के संस्थापक सदस्य के रूप में फिजी का स्वागत किया है। अमेरिकी नेतृत्व वाले इस समूह में अब पूर्वोत्तर और दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया, ओशिनिया और प्रशांत द्वीप समूह के देश शामिल हो गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा

सलाहकार जेक सुलिवन ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में फिजी के अहम योगदान को रेखांकित किया। उन्होंने एक बयान में कहा, पूरी दुनिया में, हम एक स्वतंत्र, खुले और समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को लेकर एकजुट हैं।

भू-राजनीतिक शतरंज की बिसात न बने एशिया-प्रशांत: उन्होंने कहा कि फिजी के जुड़ने से आईपीईएफ अब हिंद-प्रशांत क्षेत्र की क्षेत्रीय विविधता का प्रतिनिधित्व करता है।

बाइडन ने राष्ट्रपति के तौर पर अपनी पहली एशिया यात्रा के दौरान इस हफ्ते की शुरुआत में आईपीईएफ की शुरुआत की थी। फिजी इस समूह में शामिल होने वाला 14वां देश है जिसमें चीन शामिल नहीं है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन से जब फिजी के आईपीईएफ में शामिल होने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने पत्रकारों से कहा, एशिया-प्रशांत क्षेत्र को भू-राजनीतिक शतरंज की बिसात नहीं बनना चाहिए।

क्या है आईपीईएफ?: अमेरिका के नेतृत्व में बना आईपीईएफ वैश्विक जूरीपीपी के 40 प्रतिशत हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें एक दर्जन से अधिक देश शामिल हैं। कुछ विश्लेषक इसे क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए एक कदम के रूप में देखते हैं। सोमवार को भारत भी इस इकोनॉमिक ग्रुप का हिस्सा बन गया। इसमें ऑस्ट्रेलिया, क्नुई, भारत, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं।

## बाढ़ के बाद अफ्रीकी द्वीप पर फैल रहा रहस्यमय वायरस

एजेसी (वेब वार्ता न्यूज) साओ टोमे। अफ्रीकी द्वीप राष्ट्र साओ टोमे एंड प्रिंसिपे में पहली बार रहस्यमय डेंगू बुखार तेजी से फैल रहा है जिसे लेकर स्वास्थ्य अधिकारी चिंतित हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 15 अप्रैल से 17 मई तक, एक महीने में 100 से अधिक मामले दर्ज किए हैं। लेकिन संभवतः आंकड़ों को कम करके आंका जा रहा है। फिलहाल किसी की मौत दर्ज नहीं की गई है लेकिन रिस्पॉन्स प्लान तैयार कर लिया गया है।

डेंगू बुखार पलू जैसी एक गंभीर बीमारी है जो एडीज मच्छरों के फैलाए संक्रमण से होती है। मिरर की खबर के अनुसार डब्ल्यूएचओ ने बीमारी

फैलने के नेशनल रिस्क को शह्राई कहा है क्योंकि पिछले साल दिसंबर से भारी बारिश और बाढ़ के चलते मच्छरों के पनपने के लिए अनुकूल वातावरण पैदा हुआ है। साथ ही स्वास्थ्य केंद्रों में स्वच्छता और वाटर मैनेजमेंट की खराब व्यवस्था भी बीमारी को बढ़ा सकती है।

डेंगू का प्रकोप ऐसे समय पर फैल रहा है जब देश पहले से कोरोना वायरस, मलेरिया और डायरिया जैसी मुश्किलों का सामना कर रहा है। डब्ल्यूएचओ ने एक बयान में कहा कि दर्ज किए गए मामलों को संभवतः कम करके आंका जा रहा है क्योंकि डेंगू के ज्यादातर मामले लक्षणहीन हैं।



रामायण के अग्निबाण जैसा है पुतिन का थर्मोबेरिक बम!

एजेसी (वेब वार्ता न्यूज) कीव। यूक्रेन ने रूस पर एक बार फिर खतरनाक थर्मोबेरिक बम के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। यूक्रेन का आरोप है कि रूस ने TOS-1 रॉकेट लॉन्चर के जरिए इस बम से हमला किया है। पूर्वी यूक्रेन के डोनाबस के लेमैन इलाके में बड़े पैमाने पर इस धमाके की चपेट में लोग आए हैं। ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर ये थर्मोबेरिक बम भला क्या बला है? थर्मोबेरिक हथियार आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले पारंपरिक हथियारों से बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। इन्हें वैक्यूम बम, एयरोसोल बम या फ्यूल एयर बम के नाम से भी जाना जाता है। ये बम जहां भी फटते हैं वहां बड़ी तबाही मचाते हैं। आसपास की ऑक्सीजन को ये जला देते हैं।

## यूक्रेन को हथियार भेज कर रेड लाइन पार न करें अमेरिका

एजेसी (वेब वार्ता न्यूज)

कीव। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध लगातार जारी है। रूस अब एक बार फिर तेजी से यूक्रेन पर हमला कर रहा है। यूक्रेन ने कहा है कि रूस ने उस पर थर्मोबेरिक बम से हमला किया है। इसी के साथ उसने NATO देशों से कहा है कि उसे भी इसी तरह के हथियार दिए जाएं। लेकिन इसी बीच रूस ने अमेरिका को धमकी दी है। रूस के सरकारी मीडिया की ओर से कहा गया है कि अगर अमेरिका ने यूक्रेन को लंबी दूरी के रॉकेट या तोप भेजे तो वह रेड लाइन क्रॉस करेगा। रूसी मीडिया ने कहा कि इससे काफी गंभीर परिणाम हो सकते

रूस ने फिर अमेरिका को दी धमकी

हैं। ये धमकी ओलगा स्केबेयेवा ने दी, जो रूसी मीडिया का एक जाना-माना चेहरा हैं। उनकी ये धमकी तब आई है जब एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन अगले हफ्ते यूक्रेन को हथियारों की एक और शिपमेंट भेजने की घोषणा कर सकते हैं। इस शिपमेंट में कई लॉन्ग रेंज मिसाइल और आर्टिलरी भेजी जाएगी। यूक्रेन को डोनाबस क्षेत्र में रूस ने भारी नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन की सेना इस कारण पीछे भी हट गई है। यूक्रेन ने इसी तरह के हथियार मांगे थे। स्केबेयेवा ने कहा कि अगर अमेरिका ऐसा कुछ करता है तो

वे सीधे तौर पर लाल रेखा क्रॉस करेंगे। रूस को भड़काने पर किस तरह की प्रतिक्रिया आती है सभी जानते हैं। इस बात को लेकर चिंता जताई जा रही है कि अगर युद्ध ज्यादा बढ़ता है तो अमेरिका कहां तक यूक्रेन की मदद करेगा। इसके साथ सबसे बड़ी चिंता ये है कि अगर अमेरिका की तरफ से हथियार दिए जाते हैं तो यूक्रेन इनका इस्तेमाल देश में मौजूद रूसी सैनिकों के खिलाफ करेगा या फिर रूस पर हमला करने के लिए करेगा।

ये हथियार यूक्रेन भेज सकता है अमेरिका: अमेरिका यूक्रेन में खास दो हथियारों को भेज सकता है। इसमें M270 MLRS और M142 HIMARS हैं।

नॉर्वे के इलाके में घुस रहे थे रूसी लड़ाकू विमान!

एजेसी (वेब वार्ता न्यूज) हेल्सिंकी। यूक्रेन युद्ध के बीच फिनलैंड और स्वीडन ने नाटो में शामिल होने की घोषणा करके क्रेमलिन को चौंका दिया है। इसके बाद से ही नॉर्डिक देशों और रूस के बीच तनाव बढ़ रहा है। नाटो के लड़ाकू विमानों ने नॉर्वे और फिनलैंड की सीमा के पास दो रूसी विमानों को खदेड़ दिया जो कथित तौर पर क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहे थे। नॉर्वेजियन वायु सेना ने गुरुवार को अपने हवाई क्षेत्र के पास एक मिकोयान मिग-31 फॉक्सहाउंड और एक सुखोई एसयू-24 फेंसर जेट को रोका। द सन की खबर के अनुसार 18 मई को फिनलैंड ने नाटो सदस्यता के लिए औपचारिक तौर पर अर्ज़ाई कर दिया था। वहीं स्वीडन ने भी स्पष्ट कर दिया है कि वह सैन्य गठबंधन में शामिल होने का इच्छुक है। फिनलैंड और रूस के बीच लंबी भू सीमा है और अगर फिनलैंड नाटो में शामिल होता है तो रूस के साथ पश्चिमी सैन्य गठबंधन की सीमा दोगुनी हो जाएगी। इससे पहले रूस ने चेतावनी देते हुए कहा था कि उसे जवाबी कार्रवाई के रूप में सैन्य कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है।